

दिल्ली में निष्पक्ष व्यापार पर बैठक

लेखक- सीमा बाथला और अभिषेक झा (प्रोफेसर, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II
(अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

6 मई, 2019

“विश्व व्यापार संगठन के मंत्री-स्तरीय लघु बैठक में, विकासशील देशों को स्थिर और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार के लिए एक ठोस कदम उठाना चाहिए।”

भारत 13-14 मई, 2019 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दूसरी मंत्री-स्तरीय लघु बैठक की मेजबानी करेगा। वैश्विक व्यापार में विकासशील और कम विकसित देशों के हितों पर चर्चा करने के लिए, इस अनौपचारिक बैठक में अमेरिका द्वारा लगाये जा रहे आरोपों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहाँ अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इन अर्थव्यवस्थाओं (विकासशील और कम विकसित देश) को छूट से अधिक लाभ होता है जो कि अधिक गरीब देशों के लिए होता है।

कुल मिलाकर, यह कजाकिस्तान के अस्ताना में जून 2020 के लिए निर्धारित 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक साझा एजेंडा सेट करने के लिए एक तैयारी बैठक हो सकती है। हालांकि, 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (ब्यूनस आयर्स, दिसंबर 2017) 164 डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने के प्रयासों के बावजूद ध्वस्त हो गया था। अमेरिका ने सब्सिडी में कमी से इनकार कर दिया है और साथ ही सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए एक बारहमासी समाधान खोजने के लिए अपनी प्रतिबद्धता से भी मुकर गया है। वास्तव में, इस तरह के गतिरोध ने कई व्यापार विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या यह विश्व व्यापार संगठन के अंत की शुरुआत है।

ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि मंत्रिस्तरीय बैठकों के पहले के परिणामों के बावजूद, दिल्ली में होने वाली बैठक विश्व व्यापार संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। इस बार कि चर्चा में संरक्षणवादी उपाय, डिजिटल व्यापार, मत्स्य पालन, सब्सिडी, पर्यावरणीय मुद्दे, मानकीकरण और स्वास्थ्य-संबंधी और अन्य मामले मुख्य रूप से निवेश सुविधा के लिए बातचीत और समझौते जैसे मुद्दे शामिल हैं।

अंतराल को पाटना

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन ने प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) की जगह ले ली है, जो मुख्य रूप से व्यापार हितों पर तनाव को दूर करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दुनिया की विकासशील और कम विकसित अर्थव्यवस्थाएं (जो सौदेबाजी में थोड़ी कमजोर थीं) अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं (जो बातचीत में प्रभावशाली थीं) के बाजार तक पहुंच हासिल करने में असमर्थ रही थीं, खासकर तब जब कृषि जिंसों की बात आती है। 1980 के दशक के अंत में और फिर 2017 में कृषि व्यापार वार्ताओं के मुद्दे पर गतिरोध, कोई नई बात नहीं थी। अपने शासन में कृषि शासन को अनुशासित करने के लिए विकसित देशों (यूरोपीय संघ और अमेरिका) और विकासशील देशों (मलेशिया, ब्राजील और भारत) के बीच मतभेद अभी तक जारी हैं, जिससे विश्व व्यापार संगठन के व्यापक विकास के एजेंडे को खतरा है।

बाजार की विफलता और अन्य अनिश्चितताओं की स्थिति में विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को समर्थन देने के कारण व्यापार से विकासशील देशों की उम्मीदें भी बंध जाती हैं। सब्सिडी के माध्यम से समर्थन कमोडिटी की कीमतों में विकृतियां लाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा सब्सिडी की मात्रा 300 डॉलर से 325 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष तक भिन्न हो सकती है, जो कि विकासशील देशों के लिए अनुमान से कहीं अधिक है।

चिंता का एक और बिंदु यह है कि विकसित देशों ने कड़े नॉन-टैरिफ उपायों (NTM, एनटीएम) को डिजाइन और कार्यान्वित किया है, जिसने गरीब देशों द्वारा निर्यात करने में आने वाली समस्याओं को और अधिक गहरा बना दिया है। एनटीएम महत्वपूर्ण रूप से ट्रेडिंग की लागत को जोड़ते हैं। हालांकि, कई एनटीएम के साथ अधिग्रहण की लागत निर्यातकों के बीच विषम है क्योंकि अनुपालन उत्पादन सुविधाओं, तकनीकी जानकारी और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। इसलिए, ये देश अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं और शायद ही कृषि, वस्त्र और सहायक जैसे तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों से लाभ उठाते हैं।

विकासशील देश इन मुद्दों पर गतिरोध को तोड़ने के लिए तैयार हैं और वैश्विक व्यापार मंडल के जनादेश को झटका देने के लिए एक साझा आधार तैयार कर रहे हैं। भारत, विशेष रूप से, व्यापार के मुद्दों पर सदस्यों द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई और डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रणाली के एक प्रस्ताव पर संशोधन चाहता है। उम्मीद यह है कि बैठक में वैश्विक ज्ञान जैसे कॉर्पोरेट मानदंड से संरक्षण, सब्सिडी, ई-कॉमर्स के माध्यम से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और गरीब अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष और अंतर उपचार की निरंतरता के लिए वैश्विक मानदंडों जैसे मुद्दों पर नीतिगत मार्गदर्शन हो सकता है।

गतिरोध तोड़ना

महत्वपूर्ण रूप से, यदि विकासशील और कम विकसित देशों के हितों को संबोधित नहीं किया जाता है, तो कई चीजें वर्तमान में और भविष्य में कमजोर पर जाएंगे। उदाहरण के लिए, 10वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नैरोबी, दिसंबर 2015) में कृषि व्यापार पर जोर दिया गया था। लेकिन यह भारत और अफ्रीका सहित अधिकांश कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक झटका था, जब विकसित देशों ने गरीबों के लिए डिजाइन किए गए खाद्य सुरक्षा के अपने मॉडल को सीधे चुनौती दी।

2017 में ब्यूनस आयर्स में इसी तरह का एक परिणाम देखने को मिला था। विकसित देशों ने नए मुद्दों को निवेश की सुविधा, ई-कॉमर्स के लिए नियम, लिंग समानता और मत्स्य पालन पर सब्सिडी जैसे क्षेत्रों को तैयार करने के लिए गठबंधन तैयार किया, जबकि अधिकांश विकासशील राष्ट्र इसे पूरा करने में असमर्थ थे। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स 1998 में जिनेवा में दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद एक प्रमुख एजेंडा रहा है।

यह ई-कॉमर्स और मौजूदा समझौतों के बीच संबंधों पर ध्यान देने के साथ वैश्विक ई-कॉमर्स की जांच के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए सहमत हुआ था। जिसके बाद सम्मेलन में एक बड़ी बहस पैदा हो गयी, क्योंकि कई मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों ने इसका विरोध किया और चिंता जताई कि इसे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों द्वारा लाया गया है। अतर्निहित डर यह था कि इससे डेटा तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो जाती है, जिसे तब विकसित राष्ट्रों द्वारा अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, मुख्य रूप से यू.एस. द्वारा।

दिल्ली की बैठक सफल हो सकती है यदि सदस्य इन मुद्दों पर एक अभिसमय तरीके से बातचीत करें। विकासशील देशों के लिए समय आ गया है कि वे अपनी चिंताओं के लिए आवाज उठाएं और बहुपक्षीय व्यापार के लिए एक स्थिर और पारदर्शी वातावरण पर जोर दें। भारत को अनसुलझे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और नए लोगों को संबोधित करने के लिए अपना होमवर्क करना चाहिए जो विकसित देशों के लिए मुख्य रूप से निवेश सुविधा हैं। डब्ल्यूटीओ को बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि देशों को व्यापार नियमों को तैयार करने और असहमति वाले मामलों को एक जगह लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच की आवश्यकता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

क्या है?

- विश्व व्यापार संगठन का इतिहास 15 अप्रैल, 1994 से प्रारम्भ होता है जब मोरक्को के एक शहर "मराकेश" में चार दिवसीय वार्ता प्रारम्भ हुई थी।
- इस सम्मेलन की अध्यक्षता "प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता", जिसे "गैट/GATT" कहते हैं, के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने की थी।
- इसी सम्मेलन में "गैट" को नया नाम "विश्व व्यापार संगठन/World Trade Organization/WTO" दिया गया। यह संगठन 1 जनवरी, 1995 से अस्तित्व में आया। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष इटली के एक प्रमुख व्यवसायी रेनटो रुगियरो (Renato Ruggiero) बनाए गये।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) वास्तव में विश्व की भावी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने वाला एक दस्तावेज है, जो गैट के पुराने स्वरूप में संशोधन कर व्यापार का विस्तार कर रहा है।

विश्व व्यापार संगठन और गैट

- विश्व व्यापार संगठन का मूल "प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता"/GATT, (General Agreement on Tariffs and Trade) में निहित है। गैट की स्थापना 1948 में मूलतः 23 संस्थापक देशों द्वारा की गई थी जिनमें भारत भी एक था।
- गैट के तत्वावधान में हुई आठवें दौर की वार्ता (1986-1994) के फलस्वरूप 1 जनवरी, 1995 को "विश्व व्यापार संगठन" (World Trade Organisation) का जन्म हुआ, जिसे "उरुग्वे दौर" के नाम से जाना जाता है। इसके पहले गैट केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित था।
- उरुग्वे दौर की वार्ता में कई नए समझौतों पर भी बातचीत हुई, जिनमें सेवा व्यापार का आम समझौता और बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार से जुड़े पहलुओं पर समझौते हुए, जो अब मूल संगठन "विश्व व्यापार संगठन" में समाहित हो गये हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है और इसके वर्तमान में भारत समेत 164 सदस्य देश हैं। इससे जुड़ने वाला नवीनतम देश अफगानिस्तान है।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में मुक्त, अधिक पारदर्शी तथा अधिक अनुमन्य व्यापार व्यवस्था को स्थापित करना है।
- विश्व व्यापार संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है। इसके समझौतों की सदस्य देशों के सांसदों द्वारा पुष्टि की गई है। विश्व व्यापार संगठन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है।
- महत्वपूर्ण फैसले सदस्य देशों के निर्दिष्ट मंत्रियों द्वारा किये जाते हैं। ये मंत्री हर दो साल में कम-से-कम एक बार जरूर मिलते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के पास विभिन्न देशों के व्यापारिक मतभेदों को सुलझाने की शक्ति प्राप्त है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

- विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है:
- विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएँ प्रदान करना।
- व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार-विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।
- विवादों के निपटारे से सम्बंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।
- व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से सम्बंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।
- वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक से सहयोग करना, तथा विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

WTO के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- विश्व व्यापार संगठन की निर्णायक संस्था इसके सदस्य देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसकी दो वर्ष में बैठक होना अनिवार्य है। यह सम्मेलन बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर निर्णय कर सकता है।
- विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं। दिसम्बर, 2017 में WTO का 11वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेटीना की राजधानी Buenos Aires शहर में आयोजित हुआ था। WTO का पहला सम्मेलन सिंगापुर में दिसम्बर 1996 में हुआ था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है।
2. WTO से जुड़ने वाला नवीनतम देश बुरुंडी है।
3. WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) 1 और 2
- (c) 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

1. Consider the following statements-

1. World Trade Organization is an international organization that forms rules for world trade.
2. The latest country joining WTO is Burundi.
3. The headquarter of WTO is situated in Bern the capital of Switzerland.

Which of the above statements is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) 1 and 2
- (c) 2 and 3
- (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- WTO में एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (AMS) विकासशील देशों द्वारा सब्सिडी का सबसे विकृत व्यापारिक स्वरूप क्यों माना जाता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

Q. Why is Aggregate Measurement of Support (AMS) in WTO considered the most distorted trade form? Discuss. (250 Words)

प्रश्न:- डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत निवेश तथा ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों को शामिल किये जाने से अमीर राष्ट्रों एवं गरीब राष्ट्रों के मध्य बनी खाई के कम होने की बजाय और बढ़ने की संभावना है। मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Q. There is a possibility of increasing divide between wealthy and poor nations instead of decreasing due to the inclusion of issues like - investment and e-commerce under WTO. Evaluate. (250 Words)

नोट : 4 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।